Postal Registration No. CHD/0107/2021-2023 Posted at MBU Chandigarh RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 21 अंक 01 30 जनवरी, 2021 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से

2020 बनाम 2021 की चुनौतियां

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

वर्ष 2020 में भारत के सामने अनेको चुनौतियां आन खडी हुई है और अब नए साल में भी चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही। नोटबंदी से लगे बुरे दिन साल दर साल नई चुनौतियों के साथ उभर रहे हैं। इन सर्द भरी रातों में देश का अन्नदाता इंसाफ मांगने के लिए सडकों पर है और देश का प्रशासक दल मौन बैठा है। देश आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह बदहाल है। विदेश नीति के मामले में भी भारत दुश्मनों से घिरा बैठा है।

चीन, नेपाल, भुटान और पाकिस्तान का उभरता गठबंधन भारत के चिंताओं का सबब है। अमेरिका से ट्रंप का जाना, बाइडेन का आना और ट्रंप के चुनाव प्रचार में मोदी जी का शामिल होना सब अब भारत के लिए परेशानी बनने वाले हैं। भारतीय कुटनीति द्वारा अमेरीका में वर्ष 2019 के स्पेशल टैक्सास, ईवएन्ट होवडी मोडी व फरवरी 2020 के मोटेरा, नमस्ते ट्रंप आदि द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार करना भी काफी रोषपूर्ण रहा है। 2020 में अमेरिकी चुनाव के संबंध में भारतीय विदेष मंत्री द्वारा डेमोक्रेट फारेन रिलेशन कमेटी के निंमत्रण को ठुकराया जाने से भी काफी विरोधाभाष उत्पन्न हुआ और मई 2020 में चुनाव पूर्व वार्तालाप में राष्ट्रपति बिडेन के समर्थकों की विडोन गैंग कहकर टी वी पर गलत प्रचार किया गया। यू0के0 की प्राईवेसी एवं सिक्योरिटी रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्र को इंटरनैट शटडाउन के कारण वर्ष 2020 में 2.8 बिलियन डालर का नुकसान झेलना पड़ा जो कि अन्य 20 देशों की इंटरनैट खर्चे के दोगुना से अधिक है। रूस भी उतना अच्छा मित्र अब भारत का रहा नहीं है। देश के अंदर बात करें तो बेरोजागारी बढी है, देश का अन्नदाता खुद सडकों पर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पिछले साल के मुकाबले ये साल भी कोई राहत भरा नहीं है। गत सप्ताह इकोनोमिक टाईम्स अखबार के समाचार के अनुसार भारत को विश्व में सबसे भ्रष्ट देश माना गया है।

आपको याद होगा पिछले दिनों भारत ने चीन के खिलाफ एक बडा अभियान चलाया था। उनके एप बैन किए थे, ठेकों में भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता देने की बात कही थी लेकिन क्या हम इससे चीन को पीछे छोड देंगे। भारत में लगभग दस अरब डॉलर का निवेश कर चुकी चीनी कंपनियों के लिए यह बुरा दौर है लेकिन शी जिनपिंग की नेतृत्व वाली सरकार, चीनी कंपनियों के खिलाफ भारत की कारवाइयों पर बहुत ज्यादा बेचौनी नहीं दिखाती। चीन के अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' ने लिखा है कि ऐप बैन करने से चीनी कंपनियों के कारोबार को चोट पहुंचेगी लेकिन चीन की विशालकाय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की हैसियत भारत की नहीं है। चीन और भारत आर्थिक हैसियत के दो छोर पर खड़े हैं चीन चोटी पर है और भारत तलहैटी पर है। दरअसल चीन ने अपनी किसी भी क्षमता को बड़ी तेजी से दोगुनी करने की ताकत हासिल कर ली। मसलन, चीन को 3 हजार डॉलर प्रति व्यक्ति आमदनी को दोगुना करने में सिर्फ पांच साल लगे। इंडोनेशिया के नागरिकों की औसत आय 2010 में 3000 डॉलर की हो गई थी लेकिन अभी तक इसे वह दोगुना नहीं कर पाया है। शायद 2024 तक भी वह इसे हासिल नहीं कर सकेगा। भारत के लिए भी शायद ये स्वप्न ही साबित होगा।

जब वर्ष 2020 की शुरुआत हुई, तब जनवरी माह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), वर्ल्ड बैंक तथा दुनिया के अनेक वैश्विक संगठन यह कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि वर्ष 2019 की आर्थिक निराशाओं को बदलते हुए वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन सुधरेगा और विकास दर तेजी से बढ़ेगी, लेकिन कोविड–19 के कारण ऐसी सब उम्मीदें धरी रह गई। कोरोना संक्रमण ने दुनिया के साथ–साथ देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन में हाहाकार मचा दिया। देश में फरवरी 2020 के बाद जैसे–जैसे कोविड–19 की चुनौतियां बढ़ने लगी, वैसे–वैसे देश में अकल्पनीय आर्थिक निराशा का दौर बढ़ने लगा। देश के उद्योग–कारोबार मुश्किलों का सामना करते हुए दिखाई दिए और इनमें रोजगार चुनौतियां बढ़ गई। इस महामारी ने राष्ट्र को 10 साल पीछे धकेल दिया और 20 लाख से अधिक कामगार बेरोजगार हो गये है। आक्सफैम इण्डिया की एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान भारत के 100 बलियन लोगों की सम्पति में 35 प्रतिशत क वृद्धि हुई और दूसरी तरफ गरीब वर्ग को कोरोना की सबसे बड़ी मार नौकरी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के नुकसान के तौर पर झेलनी पड़ी। अप्रैल 2020 मास में मात्र 1 घन्टें में 1,70,000 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और देश की कुल 122 मिलियन नौकरियों में से 75 प्रतिशत नौकरियां समाप्त हो गई। सबसे अधिक परेशानी व मानसिक पीड़ा देश में निर्माण कार्यों से संबंधित व फैक्ट्री कार्यकत्ताओं को झेलनी पड़ी, लेकिन अमीरो के पास कोरोना के कारण इतना धन इक्कट्ठा हो गया कि राष्ट्र के सबसे अधिक धनाड़य 11 व्यक्तियों मनरेगा स्कीम को 10 वर्ष तक अपने व्यक्तिगत स्तर पर चला सकते है।

देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2020–21 में सकल

शेष पेज–2 पर

शेष पेज–1

घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 7.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। उनका कहना है कि कोविड–19 महामारी की वजह से राजस्व संग्रह घटने से राजकोषीय घाटा अनुमान से कहीं ऊपर रहेगा। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान 3.5 प्रतिशत रखा गया है। इस लिहाज से राजकोषीय घाटा बजट अनुमान से 100 प्रतिशत अधिक रहने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020–21 के आम बजट में राजकोषीय घाटा 7.96 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। इसी तरह वित्त मत्री ने बजट में सकल बाजार ऋण 7.80 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान रखा था। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव लंबे समय तक झेलना होगा। फिच रेटिंग्स ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष (2021–22) में भारतीय अर्थव्यवस्था 11 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज करेगी लेकिन उसके बाद 2022–23 से 2025–26 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सुस्त पड़कर 6.5 प्रतिशत के आसपास रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी में फिच रेटिंग्स ने कहा, "आपूर्ति पक्ष के साथ मांग पक्ष की अड़चनें मसलन वित्तीय क्षेत्र की कमजोर स्थिति की वजह से भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर महामारी के पूर्व के स्तर से नीचे रहेगी"। अतः अच्छे दिनों की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

इसके अलावा अगर युवाओं को रोजगार देने की बात हो तो उसमें भी भारत की हालत पतली होती जा रही है और इस साल भी सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी इलाके में हर दस में एक व्यक्ति इस समय बेरोजगारी की मार झेल रहा है। भारत में लॉकडाउन में ढील देने के बाद रोजगार के मोर्चे पर जून के मुकाबले जुलाई 2020 में बेहतर आंकड़े सामने आए थे। उम्मीद की जा रही थी कि अनलॉक के बाद धीरे–धीरे रोजगार के आंकड़े और बेहतर होंगे, लेकिन अगस्त 2020 के आंकड़ों ने एक बार फिर निराश किया है। जुलाई के मुकाबले अगस्त 2020 में रोजगार के अवसर घटे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) की एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त 2020 में भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में बेरोजगारी दर 8.35 फीसदी दर्ज की गई, जबकि पिछले महीने जुलाई में इससे कम 7.43 फीसदी थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सितंबर 2020 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में बेरोजगारी दर 11.9 फीसदी है। वहीं, दिल्ली में बेरोजगारी दर 12.5 फीसदी और राजस्थान में 15.3 फीसदी है। आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा में बेरोजगारी दर 32.5 प्रतिषत है। वहीं, हिमाचल प्रदेश में ये दर 12 फीसदी, उत्तराखंड में 22.3 फीसदी, त्रिपुरा में 17.4 फीसदी, गोवा में 15.4 फीसदी और जम्मू–कश्मीर में 16.2 फीसदी है। गौरतलब है कि 2019–20 में कृषि में विकास दर 4 फीसदी रही थी। सेवा क्षेत्र की हालत तो और भी खस्ता है, जाहिर है होटल, पर्यटन सबका हाल खराब है। विनिर्माण यानी मैन्यूफेक्चरिंग में भी तेजी लाए जाने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना की एक खास भूमिका रही है उसे कैसे मजबूत किया जाए, यह देखना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में रोजगार दोबारा धीमे–धीमे पटरी पर लौट रहा है, खासकर असंगठित क्षेत्र का रोजगार फिर पटरी पर लौट रहा है। इसे हर हाल में बनाए और बचाए रखने की जरूरत है, इसलिए समय–समय पर दोबारा लॉकडाऊन लगने की जो आशंकाएं और खबरें आती हैं, उनका सख्ती से खंडन किए जाने की जरूरत है। हां, कोरोना के मोर्चे पर ढिलाई घातक साबित होगी। क्योंकि यह तो साबित हो चुका है कि कोरोना सिर्फ स्वास्थ्य संकट के तौर पर ही सामने नहीं आया, बल्कि कोरोना आर्थिक महामारी का जनक भी साबित हुआ है।

देश में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी विशिष्ट व्यक्ति भाग नहीं ले रहा है। पहली बार देश का अन्नदाता गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी में अपने ट्रक्टरों के साथ रोष रैली निकालने पर मजबूर है अतः राष्ट्र पर किसान–कामगार–काश्तगार विरोधी होने का दाग प्रथम बार वर्ष 2021 में लगा है। 21 व 22 जनवरी को बहादुगढ़ में टिकरी बॉर्डर व सोनीपत में सिघु बॉर्डर पर लेखक द्वारा स्वयं आखें देखा हाल ये है कि आंदोलनकारी किसानों में 3 वर्ष की आयु से 80–90 साल तक के सभी वर्गों के नागरिक शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक दशक से समस्त ग्रामीण भारत सहपरिवार हाईवें की सड़कों पर अपना आशियाना बसा चुका है। यदि सरकार ताकत के बल पर आन्दोलनकारियों को हटाती है तो इसके परिणाम घातक होंगे व तमाम ग्रामीण समाज तहस–नहस हो जायेगा।

विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी पिछले साल के मुकाबले इस साल चुनौतियां कम नहीं है। चीन पाकिस्तान के साथ नेपाल को भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा है। पिछले साल से कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख को लेकर भारत का नेपाल से टकराव बना हुआ है। नेपाल का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत की ओर से जारी किए गए नए नक्शे में विवादित जगहों को भारत के हिस्से में दिखाया गया है। इसके बाद नेपाल ने इन तीनों इलाकों को अपने हिस्से में दिखाते हुए देश का नया नक्शा प्रकाशित किया। इस नक्शे को नेपाली संसद के निचले सदन ने मंजूरी दे दी है। भारत और पाकिस्तान में भी कश्मीर को लेकर तनाव हमेशा ही रहा है। पिछले साल कश्मीर से अनुच्छेद 370

हटाए जाने के बाद दोनों देशों के रिश्ते और भी बिगड़े हैं। गिलगित–बाल्टिस्तान में चुनाव कराने को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद भारत ने न्यूज चैनल्स पर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर (पीओके) के मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया था। इसके जवाब में पाकिस्तानी रेडियो पर भारत प्रशासित कश्मीर के मौसम का हाल बताया जाने लगा था। भारत पाकिस्तान, चीन व नेपाल तीनों पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद को लेकर जूझ रहा है। भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल के साथ रोटी–बेटी का रिश्ता है और मसला बातचीत से हल होगा। इसके बाद भी नेपाल के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं, सीएए और एनआरसी के मसले पर बांग्लादेश से भी भारत के संबंधों में खटास आ गई थी। नागरिकता के कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन और गृह मंत्री असद उज्जमान खान ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया था। इस साल भी इस मसले पर भारत को जूझना होगा। कोरोना वायरस से लड़ाई और गिरती अर्थव्यवस्था के बीच सीमा पर पड़ोसियों से तनाव भारत के लिए एक गंभीर स्थिति बन गई है। ये स्थितियां कैसे बनीं और इससे निपट पाना भारत के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा?

राष्ट्र में महिला विरूद्ध अपराधों में भी वृद्धि हुई है और 3–6 वर्ष की बच्चियों के साथ भी बलात्कार के घिनौने अपराध बढ़े हैं और इन अपराधों में 10 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि हुई है। इस दौरान बंगलौर दंगा 2020, जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी हमला, केरल गोल्ड समग्लिंग केस, दिल्ली दंगे 2020, हाथरस गैंग रेप व हत्या, पटना भाबुआ इंटरसिटी गैगरेप, अमसीपोरा मर्डर आदि ऐसे मुख्य घिनौने अपराध हैं जिससे राष्ट्र की साख को उभारना जरूरी है। इस वर्ष के दौरान सी बी आई द्वारा बैंक फ्राड के 190 केस दर्ज किए गए, जिनमें 60 हजार करोड़ की अनियमितताएं पाई गई। लगभग एक दर्जन केसों में बड़ी कंपनियों के उच्चधिकारियों द्वारा एक हजार करोड़ की बैंकों से धोखाधड़ी की गई। लॉक डाऊन के दौरान केवल 6 मास में सी बी आई ने 14400 करोड़ से ऊपर के 40 केस दर्ज किए। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 30 जून तक 1.85 लाख करोड़ के बैंक फ्रॉड दर्ज हुए।

गत वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पास किए गए सभी कानून विवादों की गिरफत में रहे हैं जिसमें तीन कृषि कानून प्रमुख हैं जिनको पास करने के लिए विपक्षी दलों तथा किसान संगठनों की कोई राय नहीं ली गई और लाक डाउन के आड़ में बहुमत के आधार पर जल्दबाजी में कृषि विरोधी कानून पास कर दिए जिसका परिणाम किसान वर्ग की तबाही बना हुआ है। इन कानूनों के खिलाफ राष्ट्र के बुद्धिजीवी वर्ग, खिलाड़ियों, संगीतकारों, लेखकों, सैनिक उच्चधिकारियों ने अपने सम्मान पदक तक सरकार को वापिस कर दिए हैं। भारत सरकार के 98 पूर्व आई.ए.एस. अधिकारियों ने इन कृषि कानूनों के खिलाफ अपना रोष प्रकट करते हुए किसान हित में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनको रद्द करने की मांग की है। लेकिन इसके बाद भी वह कानून का वर्तमान फ्रेम बरकरार रखना चाहती है। यह कानून से ज्यादा सरकार की साख और अहम का मामला लगता है। इसके इलावा पहली बार राष्ट्र में पत्रकारों, संगीतकारों, विशिष्ट नागरिकों व न्यायविदों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमें दर्ज किए गए जो कि सरकार के एकाधिकार को दर्शाता है। वर्ष 2009–2014 से लगातार प्रजातंत्र प्रणाली में जनता का अविश्वास बढ़ा है। इस अवधि में सरकार द्वारा 71 बिल चयन समिति को विचार हेतू भेजे गए। तत्पश्चात 16वीं लोकसभा में वर्ष 2014–2019 के दौरान 25 और वर्ष 2019 में केवल 17 बिल चयन समिति के विचार हेतू भेजे गए और वर्ष 2020 के दौरान एक भी बिल चयन समिति के समक्ष विचार के लिए नहीं रखा गया। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि केंद्रीय सरकार का संसदीय प्रणाली से विश्वास उठता जा रहा है। अगर इन तीन कृषि बिलों को विचार हेतू चयन समिति को भेजा जाता तो आज किसान आंदोलन के विरोध स्वरूप सैंकड़ों किसानों की बेमौत हादसों की नौबत नहीं आती।

गत वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पुरातत्व विभाग द्वारा संजोकर रखी गई पुरानी धरोहर के बदलाव में भी अवांछित निर्णय लिए गए। राष्ट्र की एक सौ साल पुरानी धरोहर बिल्डिंग को तोड़कर नया संसद भवन बनाया जाएगा जिस कारण 20 हजार करोड का अतिरिक्त खर्च होगा जबकि आर्थिक मंदी के दौर में एक हजार करोड़ खर्च करके पुरानी धरोहर–बिल्डिगों को संवारा जा सकता है और पुरातत्व विभाग का करोड़ों रूपया बचाया जा सकता है।

कृषि व्यवस्था को व्यवस्थित रखने विशेषकर छोटे काश्तकारों की आर्थिक दशा की उचित व्यवस्था के लिए अमेरिका, चीन में प्रत्येक पांच साल के लिए कृषि बिल की व्यवस्था की गई है, जिसमें किसान की कृषि लागत पर भारी सब्सिडी दी जाती है। अमेरीका में वर्ष 2018 के कृषि बिल में कृषि के लिए अगले 10 वर्ष के लिए 867 बिलियन डालर के बजट के साथ–साथ किसान की आय तथा पोषक स्कीमों के अनेकों प्रावधान किए गए। भारत के वर्तमान कृषि कानूनों के खिलाफ बढ़ रहे विरोध के कारण कैनेडा जैसे प्रगतिशील राष्ट्र में भी किसान अपने अस्तित्व के बचाव हेत कृषि लागत पर सब्सिडी व आयात पर राहत की मांग कर रहे हैं इसलिए भारत में कृषि व्यवस्था के सुधार के लिए समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवादित कृषि कानूनों पर निर्णय देने की प्रक्रिया से यह समस्या ज्यादा विकट होगी क्योंकि किसी भी पारित कानून को सांसद द्वारा ही बदला जा सकता है। किसी भी कानून को समर्थन देने के लिए संविधान के

हम आजाद तभी पाते हैं, जब हम अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मूल्य चुका देते हैं। – रवीन्द्रनाथ टैगोर

अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार करने की अभी तक कोई परंपरा नहीं है और इन कानूनों से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी तक कोई कारगर आदेश नहीं दिए गए। भारतीय संविधान के अनुसार कृषि के संबंध में कोई भी कानून पारित करने का संघीय सरकार को कोई अधिकार नहीं है। कृषि का विषय राज्य सूचि में आता है और राज्य सरकार ही इस संबंध में कानून पारित कर सकती है। युनियन लिस्ट के 7वें शिड्यूल द्वारा निर्धारित 97 विषयों में कृषि विषय का कोई उल्लेख नहीं है।

निष्कर्श के तौर पर गत वर्ष राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, बेरोजगारी, सार्वजनिक जन कल्याण किसान–काश्तकार के हितों के संबंध में सर्वाधिक विरोधाभाषी व चिंताजनक रहा है जिन पर चालू वर्ष में सरकार द्वारा गंभीरता से मंथन करके कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है और विशेषकर वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन पर शीघ्रता से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान ग्रामीण राष्ट्र है जहां पर 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि व इससे संबंधित कार्यों से जुड़ी है। किसान खेत में तथा उसके परिजन, वारिस सीमा पर सुरक्षा सेनाओं में विपरीत परिस्थितियों में हम सबके उज्ज्वल भविष्य के लिए संघर्षरत हैं। जनता ने पूर्व की सरकार के कारनामों से दुखी होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया था जिस पर अब उपकार किसान–काश्तकार की समस्याओं का समाधान करके चुकाने का उचित समय है। यदि किसान–काश्तकार समृद्ध होगा तो राष्ट्र भी संपन्न होगा और एक संपन्न राष्ट्र में ही देश का उज्जवल भविष्य व स्वस्थ राष्ट्रीय सुरक्षा निहित है। अभी तक प्रधानमंत्री जनता को मन की बात सुनाते रहे हैं, अब समय आ गया है कि सरकार के मुखिया किसान के मन की बात समझकर उनके समस्याओं का शीघ्र निवारण करें। लेखक को पूर्ण उम्मीद है कि वक्त की नजाकत को देखते हुए केन्द्रिय सरकार स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के "जय जवान–जय किसान" के प्रशंसनीय नारे का सम्मान करते हुए काश्तकार व राष्ट्र हित में लंबे समय से संघर्षरत किसानों की मांगों का समाधान करके नए वर्ष की एक नई प्रेरणादायक शुरूआत करेगी और 2020 में दिल्ली की दहलीज पर पहुंचे किसान को 2021 के इंसाफ का तोहफा देगी।

डॉ0 महेंद्र सिंह मलिक
आई.पी.एस. (सेवा निवृत)
पूर्व मेजर (1971 भारत-पाक युद्ध के योद्धा),
पूर्व पुलिस महानिदेशक हरियाणा, एक किसान व
प्रधान अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति ।

निर्ममता की हदें पार करते अपराधी

– डॉ. मोनिका शर्मा

डॉ. मोनिका शर्मा हालिया बरसों में दुष्कर्म–सामूहिक दुष्कर्म जैसे अपराधों के आंकड़े ही नहीं बढ़े हैं बल्कि ऐसी घटनाओं में हद दर्जे की बर्बरता भी देखने को मिल रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बदायूं में सामूहिक दुष्कर्म के बाद 50 वर्ष की आंगनबाड़ी सहायिका के साथ दिल दहला देने वाली बर्बरता कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के इस मामले ने निर्भया के साथ हुई दरिंदगी याद दिला दी है। मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी कि इस वारदात को मंदिर में अंजाम दिया गया। परिवारजनों के मुताबिक महिला शाम को पूजा के लिए गई मंदिर थी। काफी देर बाद भी जब वापस नहीं लौटी तो वे थाने गए, लेकिन तत्परता से कोई कार्रवाई नहीं हुई। देर रात आरोपितों ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी और मृतका का क्षत–विक्षत शरीर छोड़कर भाग गए। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पसली, पैर और फेफड़े को बुरी तरह क्षति पहुंचने की पुष्टि हुई है। दरिंदगी करने वालों ने महिला के निजी अंग में लोहे की छड़ जैसी चीज भी डाल दी है। साथ ही शरीर पर भी चोट के गंभीर निशान भी मिले हैं।

दरअसल, ऐसी घटनाओं ने महिला सुरक्षा के जुड़े भरोसे के भाव को खत्म कर दिया है। नैतिक, सामाजिक और मानवीय मोर्चे पर इंसान की कुत्सित सोच और बर्बर व्यवहार को सामने ला दिया है। अब दुर्व्यवहार और दरिंदगी की कहीं कोई सीमा नहीं दिखती। इस घटना में भी महिला के शरीर को हैवानों ने बुरी तरह नोचा और कई तरह से जख्मी किया। इतना ही नहीं, उसका निजी अंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त मिला है। अफसोस कि ऐसी हैवानियत का यह अकेला मामला नहीं है। देष में छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक, ऐसी वीभत्स घटनाओं का षिकार बन रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के प्रति अपराध 7.3 प्रतिशत बढ़ गए हैं।

इन आपराधिक घटनाओं में में गौर करने वाली यह भी है कि महिलाओं से होने वाली जघन्यता लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं सख्त कानून के बावजूद लंबित मामलों की बढ़ती संख्या भी अपराधियों के हौसले बढ़ा रही है। बीते साल गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी थी कि विभिन्न अदालतों में महिलाओं के प्रति अपराध के 14 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लंबित मामले हैं। महाराष्ट्र में 1,92,200 और उत्तर प्रदेश में 1,64,720 मामले लंबित हैं। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक भारत में पिछले एक दषक में बलात्कार के जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, उनमें से केवल 12 से 20 फीसद मामलों में सुनवाई पूरी हो पाई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिदिन बलात्कार की 87 वारदातें हो रही हैं, यह किसी से छुपा नहीं कि ऐसे अधिकतर मामले आज भी रिपोर्ट तक नहीं किए जाते कभी सामाजिक पारिवारिक दबाव तो कभी रसूख वाले अपराधियों के डर से बिना रिपोर्ट के ही कई मामले दबा दिए जाते हैं। बावजूद इसके दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि दुश्कर्म के जितने भी मामले दर्ज होते हैं, उनके मुकाबले सजा की दर बहुत कम है, जबकि ऐसी वारदातों में क्रूरता मन–मस्तिष्क को उद्वेलित कर देने की सीमा तक बढ़ी है।

असल में देखा जाए तो प्रशासनिक लापरवाही बरतने वाले पुलिसर्मियों के लचर रवैये के अलावा फास्ट ट्रैक अदालतों की कमी, जांच रिपोर्ट में देरी, जांच एजेंसियों का तफ्तीश के दौरान ढिलाई वाला बर्ताव लंबित मामलों की बढ़ती फेहरिस्त के लिए जिम्मेदार है। बदायूं के हुए इस मामले में भी पुलिस महिला के परिजनों को करीब 44 घंटे तक थाने के चक्कर कटवाती रही। हैवानियत के 17 घंटे बाद भी महिला की लाश घर के बाहर पड़ी रही। हालांकि इस लापरवाही के लिए स्थानीय पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है पर ऐसी घटनाओं में परिवार को जरूरत के समय प्रशासन का सहयोग न मिले तो आगे की कार्रवाई मात्र खानपूर्ति लगती है। दुखद है कि दुष्कर्म की ऐसी भयावह घटनाओं के लिए हमारा देश दुनियाभर में शर्मसार हो चुका है। यह विडंबना ही है कि एक ओर बेटियां पढ़–लिखकर आगे बढ़ रही हैं तो दूसरी ओर उनकी सुरक्षा से जुड़े हालात डरावने बन रहे हैं। निर्भया केस के बाद तो भारत को रेप कैपिटल तक कहा गया। वैश्विक छवि धूमिल होने के अलावा ऐसी घटनाएं हमारे सामाजिक–पारिवारिक ढांचे के लिए भी चिंतनीय हैं। ऐसी असुरक्षित परिस्थितियों में बेटियों की पढ़ाई छूट जाती है। बाल विवाह जैसी कुरीति को बढ़ावा मिलता है। कामकाजी महिलाएं नौकरी छोड़ने को विवष हो जाती हैं। हमारे यहां महिलाएं अपने आंगन में सुरक्षित नहीं हैं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक करीब 31 प्रतिशत मामलों में महिला के किसी न किसी जानने वाले को ही जिम्मेदार पाया गया है।

खेतों में इतनी मायूसी क्यों?

– प्रमोद जोर्शी

किसान–आंदोलन जिस करवट भी बैठे, भारत में खेती से जुड़े बुनियादी सवाल अपनी जगह बने रहेंगे। विडंबना है कि महामारी से पीड़ित इस वित्तीय वर्ष में हमारी जीडीपी लगातार दो तिमाहियों में संकुचित होने के बावजूद केवल खेती में संवृद्धि देखी गई है। इस संवृद्धि के कारण ट्रैक्टर और खेती से जुड़ी मशीनरी के उत्पादन में भी सुधार हुआ है। अनाज में आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए हमें करीब दो प्रतिशत की संवृद्धि चाहिए, जिससे बेहतर ही हम कर पा रहे हैं, फिर भी हम खेती को लेकर परेशान हैं। खेती से जुड़े हमारे सवाल केवल अनाज की सरकारी खरीद, उसके बाजार और खेती पर मिलने वाली सब्सिडी तक सीमित नहीं हैं। समस्या केवल किसान की नहीं है, बल्कि गांव और .षि–आधारित अर्थव्यवस्था की है। गांव, गरीब और किसान को लेकर जो बहस राजनीति और मीडिया में होनी चाहिए थी वह पीछे चली गई है। भारत को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने अन्न के लिहाज से एक अभाव–पीड़ित देश की छवि को दूर करके अन्न–सम्पन्न देश की छवि बनाई है, फिर भी हमारा किसान परेशान है। हमारी अन्न उत्पादकता दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले कम है। ग्रामीण शिक्षा, संचार, परिवहन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मानकों पर हम अपेक्षित स्तर को हासिल करने में नाकाम रहे हैं।

हमारा सुस्त और अस्त–व्यस्त औद्योगीकरण गांवों की बदहाली की एक वजह है। देश की लगभग 30 फीसदी आबादी शहरों में रह रही है, जबकि चीन में 53 फीसदी शहरों में आ गई है। विकसित देशों में 80 से 90 फीसदी तक आबादी शहरों में रह रही है। दूसरी तरफ जोत छोटी, तकनीक का विस्तार न हो पाने, तकरीबन 60 फीसदी खेती

किसी चीज से प्रभावित न होना ही मुक्ति है। – स्वामी विवेकानंद

मौसम के भरोसे होने, फसल बीमा जैसी सुविधाओं की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास न होने के कारण भी समस्याएं पैदा हुईं हैं। फरवरी 2018 में प्रकाशित सीएसडीएस के भारतीय किसानों की दशा पर एक सर्वे में 64 फीसदी किसानों ने कहा कि हम खेती का काम छोड़कर शहरों में जाना चाहेंगे, बशर्ते रोजगार की गारंटी हो। ऐसा ही एक सर्वे 2013 में किया गया था, तब यह बात कहने वाले किसानों का प्रतिशत 62 प्रतिशत था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि 60 फीसदी किसान नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी खेती करें, जबकि 2013 के सर्वे में यह प्रतिशत 36 था। पिछले दो दशक में तेज आर्थिक प्रगति के बावजूद देश में कुपोषण और भूख का बोलबाला है। गरीब के पास दवाई खरीदने और इलाज के लिए पैसे नहीं होते। जब अपने खर्च कम करने होते हैं, तब वह अपने भोजन में कटौती करता है। हम अब अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। अब हमें औद्योगिक समाज के रूप में बदलना होगा।

जीडीपी में हिस्सा घटता गया सन 1950 में हमारी जीडीपी में खेती का हिस्सा 54 फीसदी था, सन 1970 में 43 फीसदी था और 1991–92 में घटकर 29.4 फीसदी हो गया। मोटा अनुमान है कि इस समय यह 16 फीसदी से कम है, जबकि देश के 55 फीसदी श्रमिक खेती में आज भी लगे हैं। अर्थव्यवस्था में खेती की भूमिका कम हो रही है ऐसा कहने का मतलब यह नहीं कि अन्न उत्पादन घट गया है, बल्कि अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र, औद्योगिक उत्पादन और गैर–कृषि कारोबार बढ़ा है। पर गैर–कृषि क्षेत्र में रोजगारों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ी है। वस्तुतः हमें खेती और उद्योगों दोनों में पूंजी निवेश और संतुलन की जरूरत है। कीमत का 20 प्रतिशत किसान को खेती हमारी ताकत है और इस ताकत को बनाए रखने की जरूरत है, पर उसके सहारे जो काफी बड़ी जनसंख्या है उसे वैकल्पिक रोजगार देने की जरूरत भी है। दुनिया में दूसरे नम्बर की खेती लायक जमीन हमारे पास है। हम कई तरह की खाद्य सामग्री के उत्पादन में दुनिया के पहले या दूसरे नम्बर पर हैं, पर प्रति एकड़ उत्पादकता में हम चीन और ब्राजील जैसे देशों से पीछे हैं। अब हमें एक और हरित क्रांति की जरूरत है। विडंबना है कि उपभोक्ता जो कीमत देता है उसका बीस फीसदी ही किसान को मिलता है। शेष रकम बिचौलियों, ढुलाई, चुंगी और खराब मौसम की भेंट चढ़ती है। इसके विपरीत यूरोप में उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत में से तकरीबन 65 फीसदी तक किसान को मिलता है।

ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास को लेकर अनेक अवधारणाएं हैं और आर्थिक रूपांतरण को लेकर कई तरह के सुझाव हैं, पर इन सब बातों के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन जैसे विचारकों का मत है कि खेती की जमीन का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल रोकना आत्मघाती होगा। अलबत्ता यह देखा जाना चाहिए कि जिस कृषि भूमि का औद्योगिक इस्तेमाल किया जा रहा है क्या उसके कारण खेती से होने वाले उत्पाद के मुकाबले औद्योगिक उत्पाद कई गुना हो। इस औद्योगिक विकास के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भीहोता है। ग्रामीण समाज में भी असंतुलन है। वहां मोटे तौर पर 60 फीसदी लोग ग्रामीण मजदूर हैं। 28 फीसदी छोटे किसान हैं, जिनके पास 0.01 से 0.40 हेक्टेयर तक जोतने लायक जमीन है। इस तरह से करीब 12 फीसदी किसानों के पास मझोली और बड़ी जोत लायक जमीन है। ज्यादातर खेत मजदूर या तो दिहाड़ी पर काम करने वाले हैं या बटाई पर खेती करने वाले। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में कुल 26.3 करोड़ परिवार खेती–किसानी के कार्य में लगे हुए हैं। इसमें से महज 11.9 करोड़ किसानों के पास ही अपनी खुद की जमीन है, जबकि 14.43 करोड़ किसान भूमिहीन हैं। भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या बंटाई पर खेती करती है। ऐसे हालात में ग्रामीण विकास पर सवाल खड़ा होता है।

खाद्य सुरक्षा नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा भी चाहिए। सरकारी अन्न खरीद सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाए रखने के लिए होती है। उसके लिए अनाज खरीदने और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की दोहरी जिम्मेदारी सरकारों की है। साठ के दशक में हमें पीएल–480 के तहत मिले अनाज के सहारे रहना पड़ा, पर हरित–क्रांति ने कहानी बदल दी। इस हरित–क्रांति में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका थी। पंजाब में काफी मात्रा में अतिरिक्त अन्न उपलब्ध है, पर बाजार की समस्या है। कृषि–क्रांति के बाद समझदारी इस बात में थी कि राज्य में तेज औद्योगीकरण होता, ताकि खेती में लगे अतिरिक्त श्रमिकों को उद्योगों में लगाया जा सकता था। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में भूमिहीनों की बढ़ी संख्या है। अन्न उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर का देश है, पर 2018 में भारत में अन्न से होने वाली प्रति व्यक्ति आय 305 अंतरराष्ट्रीय डॉलर थी, जो चीन की प्रति व्यक्ति आय 630 डॉलर की आधी से भी

कम थी। नब्बे के दशक में पूंजी के वैश्वीकरण और विश्व व्यापार संगठन के गठन के साथ कुछ नए विरोधाभास भी पैदा हुए हैं। दुनिया के ज्यादातर देश खेती पर सब्सिडी देते हैं और विदेशी सामग्री पर पाबंदियां लगाते रहे हैं, पर अब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार विदेशी उत्पादों पाबंदियां हटानी पड़ेंगी। यह तथ्य खेती से जुड़े मसलों को और जटिल बनाता है। खेती की चुनौतियां कृषि–उत्पादन के मामले में भारत का शुमार दुनिया के अग्रणी देशों में होता है। दुनिया में अनाज के चार सबसे बड़े उत्पादक देश हैं चीन, भारत, अमेरिका और ब्राजील। मोटे तौर पर चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। 2019–20 में भारत में धान का उत्पादन 11.64 करोड़ टन, गेहूँ का उत्पादन 10.22 करोड़ टन, मक्का का 2.72 करोड़ टन, दालों का 2.34 करोड़ टन और इस प्रकार खाद्यान्न का सकल उत्पादन 28.49 करोड़ टन रहा, जो 1050–51 में 5.1 करोड़ टन था। बावजूद इसके हम दालों का आयात करते हैं। पिछली फसल में चीन का गेहूं उत्पादन करीब सवा 13 करोड़ टन था। दुनिया में दूध का सबसे बड़ा और फलों तथा सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। दालों, गन्ने और कपास का अग्रणी उत्पादक है। बावजूद इस श्रेष्ठता के भारत की अन्न उत्पादकता चीन, ब्राजील और अमेरिका की तुलना में 30 से 60 फीसदी कम है। दुनिया में उपलब्ध कुल पानी का 4 फीसदी भारत में उपलब्ध है। इसमें से 90 फीसदी खेती में लगता है। भारत की खेती चीन और ब्राजील की खेती में लगने वाले पानी की तुलना में दुगने पानी को खर्च करती है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय खेती को विश्वस्तरीय बनाने के लिए तकनीक और पूंजी दोनों की जरूरत है। नए निवेश की उम्मीद नहीं भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम, अहमदाबाद के सेंटर फॉर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुखपाल सिंह के अनुसार यदि केरल जहां कभी एपीएमसी अधिनियम था ही नहीं या बिहार जिसने 2006 में एपीएमसी अधिनियम को रद कर दिया था, या महाराष्ट्र जिसने 2018 में एपीएमसी की सूची से फल और सब्जियां को हटा दिया था जैसे राज्यों के अनुभवों से देखा जाए तो यह उम्मीद करना गलत है कि इन नए कानूनों के कारण कृषि में नया निवेश आएगा। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक नीति होनी चाहिए। नए निवेश के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी, न कि केवल व्यापार में सुगमता की। अनुबंध कृषि बीज के क्षेत्र में 1960 के दशक से भारत में अनुबंध कृषि चलन में है और अन्य कृषि उपज में 1990 के दशक से पंजाब और हरियाणा जैसे कई राज्यों में पेप्सिको के साथ टमाटर और आलू की अनुबंध कृषि की जाती है। इसके अलावा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मॉडल एपीएमसी अधिनियम, 2003 और बाद में मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन उत्पाद विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017 के तहत अधिकांश राज्यों में अनुबंध कृषि की अनुमति दी गई है। तमिलनाडु मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन अनुबंध कृषि और सेवाएं (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2018 के तहत 2019 में अनुबंध कृषि के लिए एक अलग अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य था और हाल ही में ओडिशा ने भी ऐसा ही किया है।

हरियाणा की शान

– एमल यादर्व

हर साल हम 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं और वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में हर साल 16 दिसम्बर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल इस विजय की यह 50वीं वर्षगांठ है। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी सेना के योद्धाओं के साथ मिलकर पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। यह युद्ध भारत के लिए आज भी ऐतिहासिक है। इस लड़ाई में 93000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस संग्राम में पाकिस्तान को मिली करारी शिकस्त के बाद पूर्वी पाकिस्तान को आजादी प्राप्त हुई और एक नया स्वतन्त्र बांग्लादेश बना। वर्ष 1971 की इस लड़ाई में लगभग 3900 भारतीय जवान शहीद हुए थे और लगभग 9851 सैनिक घायल हो गये थे। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों ने अपना सर्वस्व बलिदान करके बांग्लादेश को आजाद करवाया था। इसके अलावा 1971 के उस दौर में लगभग एक करोड़ बांग्लादेशियों को भारत ने शरण दी थी।

इस युद्ध में जनरल सैम मानेक शा और लेटिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में रणनीतिक कदमों ने मात्र 13 दिनों की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। इस लड़ाई में मेजर होशियार सिंह ने भी अपने जज्बे से पाक सेना को पराजित करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने अतुलनीय शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जरवाल का मोर्चा

विचारकों को जो चीज आज स्पष्ट दिखती है, दुनिया उस पर अमल करती है। –विनोबा भावे

फतह किया था। लेटिनेंट अरुण खेत्रपाल की वीरता भी कम नहीं थी और वे परमवीर चक्र पाने वाले भारतीय जांबाजों में से एक थे। उन्हें यह सम्मान मरणोपरान्त प्राप्त हुआ था। तत्कालीन बिहार (अब झारखंड) निवासी लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी बटालियन के सैनिकों की रक्षा की थी। इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में उनका निधन हो गया था। उनकी बहादुरी पर सरकार ने उन्हें मरणोपरान्त परमवीर चक्र से सम्मानित किया था।

इस लड़ाई में चार सगे भाई विभिन्न मोर्चों पर लड़ते हुए पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाने में आगे रहे थे। ये भाई हरियाणा प्रांत के रेवाड़ी जिले के गांव जाटूसाना के थे। इनमें सबसे बड़े भाई नायब सूबेदार रामचन्द्र यादव उस समय भारतीय सेना की 78 मीडियम रेजीमेंट में थे। यह रेजीमेंट राजस्थान के अलवर से सिलीगुड़ी होते हुए बांग्लादेश की सीमा पर पहुंचकर अपना यौद्धिक योगदान देने में सफल रही थी। इनके दूसरे भाई सूबेदार सोहन लाल ने इसी रेजीमेंट में एजुकेशन जेसीओ के पद पर रहते हुए अपना योगदान दिया था। कर्नल शंभू दयाल नामक तीसरे भाई उस समय कालूचक में 47 एयर डिफेंस रेजीमेंट में कैप्टन के पद तैनात थे और उन्होंने पाकिस्तानी जहाजों की हालत खराब कर दी थी। भारतीय सेना की ईएमई कोर में आरमोरर के पद पर तैनात इनके चौथे भाई सूबेदार मेजर श्योताज सिंह ने मुक्ति वाहिनी के जांबाजों के हथियारों की मरम्मत करके उन्हें विशेष सहयोग प्रदान किया था।

इस युद्ध के प्रमुख कारणों पर भी एक नजर डालना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान की जो हालत कर दी गई थी कुछ उसी तरह की स्थितियां पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में आज भी विद्यमान हैं। उस समय पूर्वी पाकिस्तान की आबादी सात करोड़ तथा पश्चिमी पाकिस्तान की आबादी लगभग छह करोड़ थी। जनसंख्या की अधिकता के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान की जनता का शोषण किया जा रहा था। पाकिस्तान के बनने के बाद से ही वहां की केन्द्रीय सेवाओं, तीनों सेनाओं, उद्योग धन्धों के विकास के मामलों एवं अन्य विशेष क्षेत्रों में पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को तकरीबन 60 से 90 प्रतिशत की भागीदारी हासिल हो रही थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को 10 से 40 प्रतिशत के बीच ही संतोष करना पड़ रहा था। इस कारण दोनों के बीच तनाव बढ़ना स्वाभाविक था। पाकिस्तान में वर्ष 1970 का आम चुनाव पूर्वी पाकिस्तान के लिए काफी अहम साबित हुआ। शोषण का ही परिणाम था कि इस चुनाव में वहां की राष्ट्रीय विधानसभा की 300 में 160 सीटों पर पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर्रहमान की पार्टी आवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की।

शेख मुजीबुर्रहमान की यह जीत पाकिस्तान के सैन्य शासन को गंवारा नहीं हुई। वे नहीं चाहते थे कि मुजीबुर्रहमान रहमान उन पर शासन करें। इस कारण मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने वहां जुल्म ढाने शुरू कर दिए। इसी बीच वहां पर आजादी हासिल करने हेतु कर्नल उस्मानी के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ। इस क्रान्ति को दबाने के लिए लेटिनेंट टिक्का खां ने उन पर 25 मार्च की रात्रि में भयंकर आक्रमण कर जनसंहार किया और शेख मुजीबुर्रहमान को गिरतार कर लिया गया। यह जनसंहार लगभग 30 मार्च तक जारी रहा जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इसके बाद 31 मार्च को भारतीय संसद ने सरकार से यह मांग की कि पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों के मानवीय मूल्यों की रक्षा की जाए। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से मुक्ति वाहिनी को मदद करने की घोषणा की गई और भारतीय सेना ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। इस अवधि में पाक व चीन द्वारा कई बार भारत को धमकी भरी चेतावनी दी गईं। फलस्वरूप 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम धमकियां भी नहीं देते, परंतु भारत प्रत्येक संकट का सामना करने को तैयार है। इसके बाद दोनों देशों की सैन्य तैयारियां जारी रहीं और 3 दिसंबर 1971 को सायं पौने छह बजे पाकिस्तान ने उत्तर भारत के प्रमुख हवाई अड्डों पर अचानक हमला करके युद्ध की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय पश्चिम बंगाल में थीं। वे वहां से वापस लौटीं और रात्रि 12 बजे के लगभग पाकिस्तान को मुहंतोड़ जवाब देने का निर्णय लिया गया। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को हर क्षेत्र में पराजित किया। अन्ततः 16 दिसबर को ढाका के रेसकोर्स मैदान में पाकिस्तानी लेटिनेंट जनरल नियाजी ने अपने अलंकरण उतारकर आत्मसमर्पण कर दिया। जनरल नियाजी के आत्मसमर्पण के बाद पश्चिमी सीमा पर भी युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। इस युद्ध में जिन कारणों से भारत को विजय प्राप्त हुई वे आज भी किसी लड़ाई के लिए अनुकरणीय है। उस समय तीनों सेनाओं का आपसी सहयोग, भारतीय सेनाओं का उच्च मनोबल, आक्रमणात्मक

कार्यवाही, अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना, शत्रु को अपनी सामरिक चालों से चकित करना एवं गतिशीलता जैसे यौद्धिक सिदान्तों का विजय दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा जनरल मानेक शॉ का श्रेष्ठ एवं कुशल सैन्य नेतृत्व व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बेहतर राजनीतिक नेतृत्व ने भारत को अभूतपूर्व विजय दिलाई।

मारवाड़ के राठौरों का राष्ट्रकूटों से सम्बन्ध?

– डॉ० धर्मचन्द्र विद्यालंकार

आज हम यहाँ पर राजस्थान जोधपुर के राठौर शासकों की वंशावली पर विचार करना चाहेंगें। सर्वप्रथम तो राठौरों का सम्बन्ध संस्कृत में दक्षिण(देवगिरि) या दौलताबाद के राष्ट्रकूटों के साथ ही उनका रक्त–सम्बन्ध स्वीकार किया जाता है। क्योंकि उन्होंने वहीं पर लगभग दो–सौ तीन सौ वर्षों तक वहीं पर शासन किया है। कारण अजन्ता की गिरगुहाओं में से एक संख्या 16 वीं का निर्माण राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुर्ग के काल में ही पूर्ण हो पाया था, जिसका निम्रण का काल आठवीं से लेकर दसवीं सदी पर्यन्त कहीं जाकर पूर्ण हुआ है।

दूसरा नामोल्लेख राष्ट्रकूटों का प्रतीकात्मक अथवा सांकेतिक रूप से चन्द्रगुप्त मौर्य के शिलालेखों में भी मिलता है। जोकि अब से लगभग तेईसौ–चौबीस सौ वर्ष पुराना हैं। वहाँ पर बजाय सीधे राष्ट्रकूट के रट्ट या रड्ड़ या लाटविक भी उनको वहाँ पर कहा गया है। तो उससे भी पुरातन पाँचवी शताब्दी ईसा पूर्व में रचित पाणिनि मुनि विरचित अष्टाध्यायी में हमें सिन्ध और तत्कालीन सीस्तान किंवा वर्तमान ब्लोचिस्तान में आरट्ट जैसे जन या कबीलों का ही अधिवास मिलता है। जिनका रक्त–सम्बन्ध वर्तमान में हरयाणा–पंजाब के राष्ट्रिटक या राठी और रेढू जैसे जाटों और उनके से ही निस्तृत रोडों (मराठों) के साथ भी संभव है। यदि संस्कृत के आरट्ट शब्द का प्राकृत भाषा में हम विकार देखें तो वह अरोड(ा) भी हो सकता है। जोकि वर्तमान में अरोड़ा(खत्री) लोग हैं।

इस प्रकार से यह तो सुनिश्चित है कि सिन्ध और पंजाब(संयुक्त) के यही कबीले सिकन्दर के यूनानी औचक आक्रमण से आक्रान्त होकर ही दक्षिणी और पश्चिमी भारत की ओर अनवरत अग्रसर हुए होंगें। तीसरा एक और उल्लेख हमें राष्ट्रिक किंवा राष्ट्रकूट अथवा राठी लोगों का उल्लेख महाभारत के वनपर्व में मिलता है। जहाँ पर कि पाण्ड़व लोग अपने अज्ञातवास काल में विराटराज के यहाँ पर छद्म वेश–विन्यास में शरणागत थे। तभी जब त्रिगर्त (तीन जाट गणों) ने उनकी गायों का अपहार किया था तो गांडीव धर्नुधारी अर्जुन ने उनको उत्तर–पश्चिम प्रदेशों में वर्तमान हरयाणा के रोहतक और हिसार में खदेड़ दिया था। यही लोग हमें जाटों और वैश्यों से लेकर दलित जातियों में आज तक भी मिलते हैं।

संभवतः महाभारत में उल्लिखित त्रिगर्त अथवा तीन (त्रि) जर्तगणों का आदि निवास ही वर्तमान में तिजारा जिला अलवर(राजस्थान) रहा हो। उसको वर्तमान में भी विराट से वैराटी अथवा संक्षिप्त रूप में राठक्षेत्रा ही कहा जाता है। तिजारा से लेकर बहरोड नगर से लेकर वर्तमान विराट्नगर तक का सम्पूर्ण जनपद मध्यकाल तक भी राठ–क्षेत्रा ही कहलाता था। वहाँ से विस्थापित होकर ही राठी लोग जहाँ तक भी गये हैं उन–उन नवावासित क्षेत्रों का भी नाम राठ ही होता चला गया है। यथा, हमीरपुर जिले में भी एक क्षेत्रा का नाम राठ ही है। वर्तमान तिजारा को त्रिगर्त कमलेश्वर जैसे उपन्यासकार ने अपनी कथाकृति 'कितने पाकिस्तान' में ही बताया है। तो महाभारत के महाकाव्य से पूर्व रचित अष्टाध्यायी में त्रिगर्तों का निवास–स्थान कांगडा–कुल्लू की नदी–घाटी को ही बताया गया है। क्योंकि वहीं पर तीन–तीन नदियों किवां गर्तों का संगम–स्थल है– रावी–व्यास ओर सतलुज जैसी नदियों कांगड़ा–कुल्लू की नदी–घाटी से होकर ही गुजरती है। अतएव वहीं पर जलान धारयति इति' से जालन्धर जैसा प्राचीन नगर भी बसा हुआ है।

भले ही वे तीन गण–संघ वाद में पाणिनि मुनि के मतानुसार छः तक भी हो गये थे। अतएव वहीं पर यह सूत्रा हमें मिलता है– ''दामिनि दाण्ड़क षष्टि गर्तास्यु' आदि अर्थात् दामला(डेम्बला) या डाबडा और दांडक (दांडा) और कुण्डू जैसे तीन गणों के साथ मिलकर बाद में उनका गण–संघ षटकुलों का ही परिसंघ बन गया था। अतएव उत्तर–पश्चिम से दक्षिण–पूर्व में उनका प्रवास परवर्ती काल में कदाचित् असंभव नहीं रहा होगा। तभी परवर्ती काल(लगभग दूसरी–तीसरी शताब्दी ईसा पू०) में रचित महाभारत में उनका उल्लेख विराटनगर में ही मिलता है। अतएव बाद में वहीं से विस्थापित राष्टिक अथवा राठी लोग हमें वर्तमान काल में हरयाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक में मिलते है। तो

संभवतः उन्हीं की एक शाखा महाराष्ट्र (दक्षिण) में जाकर मालवा–राजस्थान के मार्ग से होकर देवगिरि में जाकर राष्ट्रकूट बन गई होगी।

उसके पश्चात आठवीं–नौवीं शताब्दी में हमें राष्ट्रकूटों का विशद वर्णन कान्यकुब्ज अथवा कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष के अवसर पर ही मिलता है। जबकि बंगाली पाल, गुजराती प्रतिहार एवं हलायुध वंश का वहाँ पर त्रिपक्षीय सत्ता–संघर्ष हुआ था। वैसे वंशज जाट शासक सम्राट हर्षवर्धन के निधन के पश्चात जब गूर्जर प्रतिहार वहाँ के शासक बने थे, जिन्होंने वहाँ पर नौंवी दसवीं शताब्दियों तक शासन सुदीर्घ काल तक किया था। महमूद गजनवी के आक्रमणों में उस शासन को अत्यन्त दुर्बल कर दिया था। वैसी स्थिति में प्रतिहारों के शौर्य–तेज के अस्ताचलगामी होने पर ही वहाँ पर हलायुध वंश का शासन अल्पकाल के लिए स्थापित हो गया था। तभी उसको अबल अवलोककर बंगाल के पाल–वंशज शासकों और दक्षिण के राष्ट्रकूटों में सतत सत्ता–संघर्ष कई वर्षों तक चलता रहा था। उसमें अन्त में संभवतः राष्ट्रकूटों की गहमर वाली शाखा गहरवार अथवा गहडवालों को सफलता मिल गई थी।

उन्हीं के आरंभिक शासक विनयचन्द्र और गोबिन्द चन्द्र थे। गोबिन्द चन्द्र का शासन बनारस से रींवा तक भी फैल गया था। उन्हीं के सुपुत्रा जयचन्द्र का शासन बुन्देलखण्ड के परमारों तक पर भी चलता था। उसी का सीमा–संघर्ष दिल्ली को 1160ई० में जीतने वाले पृथ्वीराज के दादा वीसलदेव और पिता सोमेश्वर से भी चलता रहा था। क्योंकि तोमर (अनंगपाल–सुलेखपालादि) कन्नौज के ही माण्ड़लिक शासक चौहानों की दिल्ली–विजय से पहले थे। अतएव उनमें परस्पर में बैर–विरोध का होना सर्वथा असहज भी कहाँ था। अधिकाँश अभिलेखों में जयचन्द के वंश को गहरवार या गहड़वाल ही बताया गया है। संभवतः मोहम्मद गौरी से चन्द्रावर के युद्ध में पराजित होने के पश्चात इसी वंश के लोग वर्तमान गढवाल और कुमायूँ मण्ड़ल के पर्वतीय प्रदेशों में प्राणरक्षार्थ प्रवासित हो गये होंगें। संभवतः यही गहरवार या गहडवाला वंश जाटों के कठवाल से गठवाले बनने वाले वंशज भी हों, क्योंकि सिकन्दर के यूनानी आक्रमण के समय पर सतलुज और रावी नदियों के तटों अथवा काठों पर बसने वाले कठवाल या गढवाले(मलिक) लोग ही वहीं से उजडकर, राजस्थान के कठूमर अथवा काठेड क्षेत्रा (भरतपुर–अलवर) से लेकर गुजरात के काठियावाड तक में जाकर बस गये थे। महाभारत के त्रिगर्तो का प्रकरण भी तभी का संभव है।

अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। राष्ट्रकूटों से बिगड़कर राठौर बनने वाले इसी राजवंश का शासन तेरहवीं चौदहवीं शताब्दियों में हम उधर धुर पश्चिम में पाली से लेकर जोधपुर (पुरातन मंडौर) की मरूभूमि अथवा मारवाड में कैसे पाते हैं। इस बात को समझना व जानना भी जरूरी होगा। पृथ्वीराज रासौ के रचयिता राजकवि चन्दरबरदाई भाट ने ही सर्वप्रथम अपनी काव्यकृति में जोधपुर और बीकानेर के राजवंशों को राठौर लिखा था। उसी के अनुकरण भी नैणसी मुहलौत और दयालदास ने भी राजस्थान की ख्यातों और परगना जोधपुर जैसे इतिहास–ग्रंथों में राजस्थानी मारवाड़–शासकों को राठौर ही मान लिया था। जबकि पृथ्वीराज–रासो में ही कन्नौज के शासकों को गहरवार या गहडवाल (गठवाले) जाट बताया गया है।

लेकिन यहाँ पर एक समस्या यह भी है कि कन्नौज के गहरवालों के विवाह–सम्बन्ध बदायूँ स्थित राठौरों के साथ दर्शाये गये हैं। अतएव इसी बात को लेकर गोपीराम शर्मा जैसे नये–नये राजस्थानी इतिहासवेत्ता ने राठौरों और गहरवालों को दो अलग–अलग राजवंश ही माना है। क्योंकि उनके मत से राजपूतों किवां मध्यकालीन राजवंशों में स्ववंश में ही विवाह–सम्बन्धों की प्रथा प्रचलित नहीं थी। परन्तु ऐसा सर्वथा असंभव भी नहीं था। बाद में गुरूगोत्रों को बचाकर राजवंशों में परस्पर में ही शादी–ब्याह होने लगे थे। गोत्रों अथवा प्रवरों को भी उनकी अलग शाखा मानकर ही उनमें एक ही वंश में शादी–ब्याह होने लगे थे। तब केवल गोत्रा या प्रवर ही बचाये जाते थे।

उदाहरणार्थ भरतपुर और करौली के जाट–राजपूत एक ही तो यादव वंश–वृक्ष की शाखाएँ हैं। उसी प्रकार से गुजरात के जामनगर के जडैजा राजा भी स्वयं को यदुवंशी ही मानते रहे हैं। ठीक उसी भांति कर्नाटक के मैसूर का वाडियार राजवंश भी स्वयं को यादव ही मानता है, होसलों के कारण। ऐसे ही पटियाला का सिख जाट राजवंश भी अपना रक्त–सम्बन्ध जैसलमेर के भाटी (यादव) राजपूतों के साथ ही स्थापित करता है। तथापि उपर्युक्त इन सभी राजवंशों में परस्पर में ही हमें प्रगाढ विवाह–सम्बन्ध रक्तशुद्धता के कारण भी दीख पडते हैं। इसलिए गोपीराम शर्मा का यह तर्क नितान्त निराधार है कि एक ही रक्त–वंश में शादी–ब्याह नहीं हो सकते। संभवतः इसीलिए हीराशंकर गौरीशंकर ओझा से लेकर जेम्स टॉड से लेकर हार्नेली तक सभी इतिहासविद कन्नौज के शासकों को चन्द्रवंशी राठौर अथवा राष्ट्रकूट ही मानते हैं।

विचार का चिराग बुझ जाने पर आचार अंधा हो जाता है। –बिनोवा भावे

जबकि गोपीराम शर्मा बजाय कन्नौज के राजवंश के मारवाडी (जोधपुर–बीकानेर) के शासकों का रक्त–सम्बन्ध बंदायू के राष्ट्रकूटों के साथ ही जोड़ते हैं। जेम्स टॉड ने यह उल्लेख किया है कि जब सिया जी राव(छोटा राजा) कन्नौज से उजड़कर लूणी नदी के निकट पाली परगने में आकर बस गया था तो पाली के ब्राह्मणों ने जोकि पशु–व्यापार किया करते थे। चौहानों के आतंक से संत्रास्त होकर ही सियाजी राव को अपनी सहायतार्थ आहूत किया था। तब उन्होंने चौहानों से उनका संरक्षण किया था। बाद में चौहानों (वाछल अथवा वत्सवंशी) वत्सल संस्कृत चौहानों के साथ सन्धि–सुलह होने पर उनके मध्य में मधुर विवाह–सम्बन्ध भी स्थापित हो ही गये थे। ऐसे ही आगे इन्हीं इतिहासकारों का एक मत यह भी है कि गुजरात के सोलंकी (चालुक्य) शासकों को सिन्ध का लाखा–मुल्तानी परेशान किया करता था। तब उसके आतंक से भाग पाने के लिए ही सोलंकियों ने सिहाजी राव राठौड़ से सहायता–याचना की थी। लेकिन उपर्युक्त मान्यता अर्धसत्य पर ही आधारित है क्योंकि लाखा–मुल्तानी का वध गुजरात के सोलंकी शासक मूलराज ने उससे पूर्व लगभग दो सौ वर्ष पहले दसवीं–ग्यारहवीं शताब्दी मं ही कर दिया था। हाँ, यह बात सत्य है कि सोलंकियों ने अन्हिलवाडा–विजय (आबू पर्वत–सिरोही–जालौर क्षेत्रा)पर चौहानों से विजय पाकर ही अवश्य राठौड राजपुत्रों से अपने शादी–सम्बन्ध स्थापित किए होंगें। क्योंकि राजनीति में शत्रा का शत्रा भी मित्रा ही माना जाता है।

फिर नाटौल–भीनमाल के चौहानों और अहिलवाड के शासकों में सीमान्त–क्षेत्रों पर अवश्य ही सत्ता–संघर्ष चलता रहता था। इसीलिए उन्होंने एक बाधक या बफर–राज्य (Bfufer State) अपने और चौहानों के मध्य में खडा करने की गरज से ही राठौरों के साथ विवाह–सम्बन्ध बना लिए होंगें। वैसे उस समय तक राठोडों की स्थिति मारवाड में उतनी मजबूत कहाँ थी कि वे इतने बडे राजवंशों की कमनीय कन्याओं को स्वकुल की रानी बना पाते। वह स्थिति तो उनकी तेरहवीं–चौदहवीं शताब्दी के पश्चात लगभग पन्द्रहवीं शताब्दी में ही कहीं जाकर बनी है। वह भी जबकि मंडौर के परिहार राजपुत्रों ने अपनी सुपुत्राी का सम्बन्धउनके साथ जोड़ दिया था और दहेज में मंडोर का दुर्गम दुर्ग भी उन्हें सहजभाव से ही तो सौंप दिया था। आज भी मंडौर (मंदसौर) अथवा मेड जाटों की पुरानी बस्ती में आरंभिक राठौर शासकों के देवालय किंवा श्मशान घाट अवस्थित हैं। राजा मानसिंह से लेकर तख्त सिंह तक के। रणमल ही राव राजा (लघुशासक) से दुर्गस्वामी बनकर राणा किंवा पूर्ण शासक बने थे। उनके ज्येष्ठ सुपुत्रा शासक जोधाजी ने ही वर्तमान जोधपुर नगर मंडौर के पश्चिम–दक्षिण में पाँच–छः मील दूर बसाया था। जिसमें मेहरगढ का दुर्गम एवं सुदृढ तथा सुन्दर दुर्ग विद्यमान है। तो बीका जी जोकि राणा रणमल के कनिष्ठ पुत्रा थे, उन्होंने ही कुरू–जांगल (बीकानेर संभाग) में आठ जाट गणराज्यों के संघ को षडयन्त्रापूर्वक पाण्डू गोदारा की आन्तरिक सहायता पाकर ही पराजित किया था। तभी सोलहवीं–सत्राहवीं शताब्दी में जाकर राठौरों किंवा राष्ट्रकूटों की दूसरी शाखा ने बीकानेर से लेकर पोखरण तक के रेगिस्तानी भूभाग पर अपना विस्तृत शासन स्थापित किया था। जोकि पश्चिम में पाकिस्तान के सिन्धु देश (सिन्ध–प्रान्त) से भी संलग्न था। उसके पश्चिमोत्तरी भूभाग में पन्द्रहवीं–सोलहवीं शताब्दियों में जैसलमेर में भाटी (यदुवंशी) राजपुत्रों का शासन स्थापित हो सका था।

मूल समस्या अब यहाँ परी यही अनसुलझी है कि ये मारवाड के राठौर उत्तरपूर्व से कन्नौज या बंदायू से चलकर यहाँ पर आकर बसे थे, अथवा ये वहाँ पर पहले से ही आबाद थे। यहाँ पर गोपीराम शर्मा एक नई जानकारी हमें यही उपलब्ध कराते हैं कि पाली नामक नगर–स्थान अथवा वर्तमान जिला मुख्यालय के निकट एक हस्तकुंडी नामक जैन–धर्म का तीर्थस्थान है। वहीं पर दक्षिण से आने वाले राष्ट्रकूट ग्यारवीं शताब्दी से ही आबाद थे। जब पाली के पालीवाल वैदिक(पणी–फणी) पशुपालक ब्राह्मणों ने मेडों (मेवों) और मीणाओं के विरुद्ध सियाजी राव राठौर से सैन्य–सहायता की याचना की थी। तभी उन्होंने वहाँ से पुरातन शिवियों अथवा (रावत) मेड़ या मेवों को अजमेर(मेरवाडा) की ओर धकेलकर उनका सबल सहाय ही किया था। परन्तु अपनी राजलिप्सा के चलते बाद में पाली परगने (तहसील) पर सियाजी ने अपना ही अधिकार कायम कर लिया था। तभी वहीं से वे प्रतिहारों की मंडौर शाखा के साथ विवाह–सम्बन्ध स्थापित करके सम्पूर्ण मरूधरा (मारवाड अंचल) में अपनी राजसत्ता का विस्तार कर सके थे। नैणसी को उदा प्रतिहार या परिहार ने सियाजी के साथ परनाया था। लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे अपना मंडौर का पुरातन सुदृढ दुर्ग दहेज में देकर उसने अपनी राजलक्ष्मी की भी वरमाला जैसे राठौरों के गले में डाल दी थी। इस विषय में मारवाडी में एक कहावत भी लोकप्रचलित है। इस लेखक ने उन्हीं राजशक्ति हीन–क्षीण दीन दशा में दलितों के रूप में पाली में अपने प्रवास में पाया था। अतएव राठौर हाथी–कुंडी के पुरातन दक्षिणी राष्ट्रकूटों के ही वंशज हैं।

जो उनका रक्त–सम्बन्ध अप्रमाणिक रूप से कन्नौज के अथवा बदांयू के गहरवारों किवां गठवाले (मलिक जाटों) के साथ जोड दिया था, चन्दरबरदाई ने उसका एकमात्रा कारण यही हो सकता है कि उस समय चारण–बंदीजन भाट अथवा ब्राह्मण ग्रंथकार राजसत्ता–सम्पन्न किसी भी राजपुरुष का रक्त–सम्बन्ध किसी भी प्रतिष्ठित राजकुल से जोड दिया करते थे। और तो क्या, उन्होंने राजपूत राजवंशों की दैवीय–उत्पत्ति सूर्य एवं चन्द्र वंश से भी दर्शाई है जोकि एक सर्वथा मिथ्या परन्तु कलित कल्पना ही है। इसी प्रकार से श्री रामचन्द्र एवं श्रीकृष्ण चन्द्र जैसे पौराणिक परन्तु अवतारी राजपुरुषों के साथ भी उनका वादायण सम्बन्ध प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपेण वे जोड़ते रहे हैं। क्योंकि राजसत्ता सम्पन्न सामन्तों को बजाय राजपुत्रा के देवपुत्रा बताकर ही तो परजीवी पुरोहित वर्ग अपनी आजीविका का अर्जन बिना किसी प्रकार के कर्मकठोर व्यवसाय के भी कर सकता था। कारण, सामन्त अथवा ठिकानेदार (ठाकुर) जोकि बडे–बडे भूसामन्त अथवा जागीरदार थे। तब वही तो पुरोहित प्रवरों के लिए ठाकुरद्वारों (मंदिरों) और पानशाला (प्याऊ) एवं धर्मशालाओं का निर्माण किया करते थे। आखिर राजसत्ता को भी अपनी शास्त्रा–सम्मत वैधता के लिए विप्रदेवों की प्रशंसा अथवा प्रशस्तियों की अत्यन्त आवश्यकता थी ही।

यहाँ पर यह भी ज्ञातव्य है कि मौर्य एवं गुप्त जेसे पहले शूद्र–प्राय शासक ब्राह्मणीय धर्मसत्ता का सबल समर्थन एवं सहाय पाकर ही तो क्षत्रिय कुलभूषण माने गये थे। वरना तो विधवा–विवाह (चन्द्रगुप्त और ध्रुवदेवी) रचाने के कारण वे पंजाब के अमृतसर के धारीवाल के धारणवंशी जाट ही तो कहलाते। 'कौमुदी महोत्सव' एवं 'देवी–चन्द्रगुप्त नाटक' में महारानी ध्रुवदेवी के बन्धु अथवा राजा के साले को (राष्ट्रिक) को वर्णवार अथवा निम्न कुलोद्भूत बताना यही तो दर्शाता है। इसी प्रकार से पूर्वमध्यकाल(7वीं–12वीं) शताब्दियों के मध्य में महाराजा हर्षवर्धन के देहपतन के पश्चात एकक्षत्रा साम्राज्य की समाप्ति के पश्चात ही उत्तर–भारत में ये नाना देशी और विदेशी रक्त वंशज राजकुल राजसत्ता में आने के कारण ही 'राजपुत्रा' मान लिए गए थे और जो किसान जातियाँ अपने ही हाथों के कृषि–कर्म किया करती थी और विधवा–विवाह रचाया करती थी, उन्हीं को सनातनी (सड़ातनी) ब्राह्मणों ने अपने द्वारा स्वहित में रचित वर्चस्ववादी स्मृति–शास्त्रों में उन्हें बजाय राजपुत्रों के दासीपुत्रा अथवा वर्षल या वर्णशंकर बता दिया था। कर्नल जेम्स टॉड ने अपने राजस्थानी इतिहास में यही सत्य तो सिद्ध किया है। अतएव राष्ट्रकूट किंवा राठौर भी राठी जाटों के ही रक्तबंधु संभव हैं। क्योंकि मंडौर को बसाने वाले मेड़ या मुंडेर जाटों को भी राष्ट्रकूट अथवा राठौर भी कई राजस्थानी इतिहासकारों ने माना है।

समाज में गहराता संकट

आज देश में समाजिक व आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। कृषि, चिकित्सा, रोजगार,मजदूरी व पर्यावरण जेसे सभी अहम क्षेत्रों में संकट के बादल छाये हैं। उद्योग धन्धे बन्द हो रहे हैं। धर्मों व जातियों के बीच नफरत फैलाई जा रही है तथा सहनशीलता का अभाव हो रहा है। मुख्य समस्याएं कुछ इस प्रकार हैं।

1. मजदूरों का शोषण

समस्या : मजदूरी इतनी कम है कि मजदूरी के परिवार का जीवन यापना बड़ी मुश्किल से होता है। श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी 178 रुपये प्रतिदिन करने का प्रस्ताव पेश किया है। अगर एक मजदूर महीने में 25 दिन मजदूरी करे तो उसे महीने में 4450 रुप्ये वेतन मिलेगा क्या एक चार आदमियों का परिवार 4450 रुपये में निर्वाह कर सकता है? स्थिति दयनीय है। अगर मजदूर एक मानवी स्तर बनाये रखने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, चिकित्सा प्राप्त करने के लिए, घर का किराया, खाना,बिजली–पानी आदि का प्रबन्ध करे तो उसे कम से कम 15,000 से 20,000 रुपये मासिक वेतन की जरुरत है।

काम करने के हालात बदत्तर हैं। न निवास की सुविधा, न स्वच्छ वातावरण, न मूलभूत सुविधाए, न दोपहर के खाने का प्रबन्ध, न कोई सामाजिक सुरक्षा व परिवार कल्याण की योजनाएँ।

सरकार जो लेबर कोड मजदूर सुधार के नाम पर लाने वाली है उनमें मालिकों की सुविधा का ध्यान रखा गया है न कि मजदूरों की सुविधाओं का । उनके लिए मजदूर यूनियन बनाना कठिन किया जा रहा है। उनके विभिन्न अधिकारों की रक्षा का कवच ढीला किया जा रहा है। एक तरह से कोड लेबर कोड न होकर मालिक कोड का काम करेंगे।

समाधान : मजदूरों की उद्योग प्रबन्धन कमेटी में भागीदारी की जाए। मजदूरी न्यूनतम 15,000 से 20,000 रुपये महीना हो। काम करने की जगह मूलभूत सुविधाएँ हो। घर से निकटतम स्कूल में मुत शिक्षा व चित्सिालय में मुत ईलाज का प्रबन्ध हो। फिर चाहे वह सुविधा सरकारी हो निजी हो। साठ साल उम्र होने पर जीवन व्यापन के लिए प्रर्याप्त पैन्शन हो। घर से

मेहनत की फसल आप ही काटेंगे, सदैव ऐसा नहीं होता। हम आम खाते हैं पर पेड़ हमने नहीं लगाए थे। –लोकमान्य तिलक

कार्यस्थल तक वाहन में मुत यात्रा का प्रबन्ध हो। यह सब देश की आज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए संभव है।

2. रोजगार के अवसर

समस्या : सीएमईआइ सर्वे में देश में 6.1 प्रतिशत बेरोजगारी, शिक्षित युवाओं में ज्यादा बेरोजगारी। रोजगार की गुणवत्ता में गिरावट। न्यूनतम वेतन भी उपलब्ध नहीं। कृषि में प्रतिशत लोग काम करते हैं तथा जीडीपी में कृषि का शेया मात्र 15 प्रतिशत है। कृषि में घाटे का सौदा होने के कारा रोजगार की समस्या विकट होना। सरकार की निजिकरण की नीति व खाली पदों को न भरना।

समाधान : सरकारी क्षेत्र में कुल रोजगार का 20 से 30 प्रतिशत मुहैय्या कराया जा सकता है। जन–सेवाओं को ठीक से उपलब्ध कराने के लिए ऐसा करना जरूरी है। सरकारी विभागों में एक ओर तो स्वीकृत पद कम हैं और दूसरी ओर देखें तो वह भी 20 से 25 प्रतिशत खाली पड़े हैं। सरकार ने ठेकेदारी प्रथा लागू की हुई है। इससे न तो टिकाऊ नौकरी मिलती हे, न ही वेतन प्रर्याप्त मिलता है। ठेकेदारी प्रथा को बंद कर स्थाई कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सभी को उचित रोजगार मिल सकता है। इसी प्रकार कृषि में किसान उत्पादन कम्पनियां व दस्ताकार उत्पादन कम्पनियां बनाकर बहुत से रोजगार पैदा किए जा सकते हैं।

3. सामाजिक कन्याय व सुरक्षा

समस्या : आर्थिक व सामाजिक असमानता। छूआछूत व भेदभाव की भरमार। जानबूझ कर व योजना के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट। इसीर प्रकार स्वास्थय सेवाओं का अभ्ज्ञाव। इन कारणों से पिछड़े व गरीबपरिवारों के बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। उचित आहार की कमी जिससे अगर पिछड़े स्कूल में पहुँच न पाते। ऊपर से वे स्ज्ञकूल व बल्कि सभी सार्वजनिक जगहों पर तिरस्कार के शिकार होते हैं। महिला बाल सुरक्षा की दुर्दशा।

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह स्कीम का विस्तार किया जाए। गाँव व शहरों में पब्लिक भोजनालय खोल जाएं व उचित दरों पर सह–भोजन का प्रबन्ध हो। सरकार द्वारा ऐसे त्यौहार जिनका किसी धर्म से तालुक न हो, सार्वजनिक तौर पर मनाए जाएं व उनमें सभी समुदायों के लोग शामिल हों इन उत्सवों में सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएं। शिक्षा संस्थाएं उच्च गुणवत्ता वाली हों महिला व बाल सुरक्षा को सक्षम बनाया जाये।

4. शिक्षा

समस्या : सरकार की निजीकरण की नीति। सरकारी स्कूलों को बंद करना व प्राइवेट को अनियन्त्रित छूट देना। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में भारी गिरावट, खासतौर से ारकारी ग्रामीण क्षेत्रों में। शिक्षा में असमानता, अध्यापकों की कमी व उनकी प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कमी तथा स्कूलों का भौतिक लचर ढांचा एवं स्कूल प्रबन्धन की खामियाँ शिक्षा जगत की मुख्य कमियां है।

समाधान : सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाना। नीजी स्कूलों की अनाप–सनाप बढ़ती फीस पर लगाम तथा अध्यापकों की संख्या वव प्रशिक्षा में बढ़ोतरी करना।

समाज में अध्यापक का मान बढ़ाने के लिए उनका वेतनमान बाकी क्षेत्रों के समकक्ष कर्मचारियों से ज्यादा करना आवश्यक है। स्कूलों की मूलभूत सुविधाएं प्रशासनिक वर्ग की सुविधा ं से अच्छी होनी चवाहिए। जैसे स्कूल की इमारत व प्रांगण लघु सचिवालयों से बेहतर हो। दिल्ली सरकार के स्कूलों से इस बारे में काफी कुछ सीख ली जा सकती है। वैसे दिल्ली के स्कूलों में भी काफी सुधार करने की जरूरत है।

5. स्वास्थ्य सेवा

स्वास्थ्य सेवाओं की आज यह हालत है कि कोई भी नागरिक सरकारी चिकित्सालयों में जाना नहीं चाहता। बस जो जाते हैं आर्थिक मजबूरी की वजह से जाते हैं। दुसरा, सरकार बिमारियों की रोकथाम के उपायों पर खर्च न करके इलाज के लिए पैसा खर्च करती है। यह पैसा भ्रष्टाचार के कारण मरीजों के इलाज के लिए खर्च न हो कर ऊपर से नीचे तक आकाओं की जेबों में जाता है। रोकथाम पर खर्च से दवाइयां व उपकरण बनाने वाली कम्पनियों को लाभ नहीं होता। सरकार की नीति स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध न करा कर बीमा कम्पनियों को प्रोत्साहित करती है। यह एक लूटमार का अच्छा तरीका है। डॉक्टर व मैडिकल स्टाफ की भारी कमी भी है।

समाधान : हर एक हजार लोगों पर एक डॉक्टर व इसी अनुपात में बाकी स्टाफ। सरकारी चिकित्सालयों की संख्या व गुणवत्ता में बढोतरी। सुदृढ़ प्रबन्धन व भ्रष्टाचार का खात्मा। बीमारियों के रोकथाम पर प्रयाप्त ध्यान। पेयजल का प्रबन्ध व साफ–सफाई को प्राथमिकता, निजी चिकित्सालयों की मनमर्जी पर लगाम।

6. कृषि संकट

समस्या : कृषि निविष्टियों (लागत) की तेजी बढ़ती कीमतें। कृषि पैदावार की कीमतों मेंब कम बढ़ोतरी। अनावश्यक खाद व दवाओं का प्रयोग। कृषि परआधारित होना। इप्राकृतिक आपदायें। कृषि उपजों की आयात व निर्यात नीति किसान विरोधी होना। मण्डियों में मिली–भगत से किसानों की फसल की लूट। कृषि मण्डी कानून की वजह से किसान मण्डी से बाहर उत्पाद न बेचने का सिस्टम। कृषि में उपयोग होने वाले पानी व बिजली का दरूपयोग। भ्रष्टाचार की वजह से ड्रीप व सपरिंकलर विधि से सिंचाई का महंगा होना। सोलर ऊर्जा, जो कृषि के लिए पम्पसेट के लिए प्रयोग हो सकती है, का सरकार

जुआ सुख, संपत्ति और समय इन तीनों का, जो जीवन के लिए अति मूल्यवान है, नाश करता है। –अज्ञात

द्वारा तुच्छ प्रावधान तथा उसमें भी भ्रष्टाचार। सोलर वृक्ष लगाने पर भी कोई ध्यान न होना।

समाधान : ऊपर दी गई समस्याओं के सामाधन बहुत आसान है बशर्ते कि सरकार की तरफ से इच्छशक्ति व नेक नियति हो। भ्रष्टाचार ही इन समस्याओं की जड़ में है। सरकार को उपयुक्त नीति बनाकर पहल करनी होगी। किसान को मण्डी की मनमर्जी पर छोड़ना उचित नही है।

7. पर्यावरण

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोश के अनुसार भारत में विकास के कार्यों में प्रदूषण होने के कारण जीडीपी का 4 प्रतिशत पर्यावरण को ठीक करने में खर्च करना पड़ता है अगर पर्यावरण को ठीक–ठाक स्थिति में बनाए रखना है। कहने का अभिप्रय यह है कि जो हम करीब 6 प्रतिशत बढ़ोतरी जीडीपी में कर रहे हैं उसमें से 4 प्रतिशत के बराबर पर्यावरण का नुकशन कर रहे हैं। हामरी हवा, पानी, मिट्टी सब प्रदूषित हो रहे हैं। इसके कारण हमारा भेजन दूषित हो रहा है। लोागों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ता है। फिर हमें सेहत को ठीक करने के लिए दवाओं पर खर्च करना पड़ता है। तरह–ततरह की बीमारियों से जूझना पड़ता है। की बढ़ती रतार, हृदय रोग इत्यादी दिन–प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए हमें हर विकाश के कार्य में प्रदूषण से बचाव के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। मौसमपरिवर्तन भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। सरकारें सिर्फ मुनाफे को ध्यान में रखकर व धन्ना सेठों की व नेता खुद की जेबें भरकर पर्यावरण के संकट को ताक पर रख रहे हैं। जब तक पब्लिक का दबाव नहीं बनता जनता का जीना दूबर हो जाए।

आवश्यक सूचना

आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि जाट सभा चण्डीगढ़, पंचकूला एवं चौ० छोटूराम सेवा सदन कटरा–जम्मु द्वारा सुरक्षा सेवाओं में कमीशन अधिकारी स्तर के चयन हेतु एन.डी.ए., आई एम.ए. व एस.एस.सी. की प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी के लिये कोंचिंग/शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह कोंचिंग कार्यक्रम सर्विस सलैक्शन बोर्ड सेवाओं के ख्याति प्राप्त व सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (सेवा–निवृत) सुरेन्द्र सिंह जून द्वारा सर छोटूराम जाट भवन, सैक्टर–6, पंचकूला में शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा जिसमें जाट सभा चण्डीगढ़, पूचकूला एवं चौ० छोटूराम सेवा सदन कटरा–जम्मु के आजीवन सदस्यों के बच्चों/आश्रितों तथा जाट समाज के बच्चों को रियायती दर से कोंचिंग दी जायेगी। यह कोंचिंग सेंटर युवाओं के व्यक्तित्व विकास हेतू उच्च शिक्षण केन्द्र के तौर पर विकसित किया जायेगा, जिसमें शिक्षित युवक–युवक्तियों को रोजगार के सुअवसर उपलब्ध करवायें जायेंगे।

इस संबंध में इच्छुक प्रतियोगी अपना नाम व पता पूर्ण विवरण सहित जाट भवन चण्डीगढ़ में कार्यालय सचिव, दूरभाष 0172–2641127, 2654932 व सर छोटूराम जाट भवन, सैक्टर–6, पंचकूला में केयर टेकर, दूरभाष 0172–2590870, मो० 9467763337 को भेज सकते है।

वैवाहिक विज्ञापन

- SM4 Jat Girl 29/5'4" BA from Kurukshetra University. GNM from Pt. Bhagwat Dayal University Rohtak. Preferred match from Tri-city. Avoid Gotras:Bankura, Mann, Narwal. Cont.: 9354839881.
- SM4 Jat Girl (DOB Nov. 94) 26/5'1" B. Com., M.Com.. NET in Commerce, B.Ed. Avoid Gotras: Gill, Goyat, Gehlawat. Cont.: 9416193949
- SM4 Jat Girl (DOB 06.06.93) 27/5'2" B.Sc. Medial, MA (English). One year diploma in German language and library. Doing D. Pharmacy. Avoid Gotras: Jattan, Dabas, Rana. Cont.: 9728308809
- SM4 Jat Girl (DOB 23.08.92) 28/5'2" B.Tech. in Electrical & Communications. GATE cleared. Avoid Gotras: Rathi, Balhara, Redhu. Cont.: 9888146931
- SM4 Jat Girl (DOB 19.08.95) 25/5'11" M.A. economics from P.U. Chandigarh. B.Ed. Working as teacher in a reputed school at Panchkula. Father Army Eexservice-man. Mother housewife. Avoid Gotras: Dalal, Kadiyan, Gawadiya. Cont.: 8054064580
- SM4 Jat Girl (DOB 06.02.92) 28/5'2.5" M.A. Economics, B.Ed. Working as dance teacher in school at Mohali. Father in Govt. service. Avoid Gotras: Nain, Sangwan, Dhaliwal, Panghal. Cont.: 7837908269
- SM4 Jat Girl (DOB 26.02.91) 29/5'5" B.D.S. Working as P.V. Scientist in Parexel International MNC at Chandigarh. Father Sub Inspector in Chandigarh Police. Own house at Chandigarh & family settled at Chandigarh. Preferred match from Tri-city. Avoid Gotras: Kundu, Malik, Sandhu. Cont.: 9779721521
- SM4 Jat Girl (DOB 04.04.92) 28/5'3" M. Tech. in Electrical & Communication from DCRUST Murthal. MBA in HR & Marketing. Working in MNC I.T. Park, Chandigarh. Avoid Gotras: Sura, Malik, Mann, Sehrawat, Siwach. Cont.: 9467864845
- SM4 Jat Girl (DOB 07.11.92) 28/5'4" B.Tech (EC), MBA (Business Analyst & Marketing). Avoid Gotras:Saharan, Dabas, Samota. Cont.: 9671922745
- SM4 Jat Girl (DOB 11.12.93) 27/5'6" B.A., MA (English). Father Inspector in Chandigarh Police. Avoid Gotras:Ahlawat, Mann, Narwal. Cont.: 9896891926, 9878901559.
- SM4 Jat Girl (DOB 05.08.94) 26/5'3" B. Tech from P.U. Working in I.T. sector at Banglore. Father A.S.I. in Chandigarh Police. Avoid Gotras:Sihag, Redhu, Naare, Khatkar. Cont.: 9417862853
- SM4 Jat Girl (DOB 25.04. 93) 27/5'4" M.Sc. Nursing. working as Lecturer at Swami Devi Dayal College of Nursing. Avoid Gotras:Pilania, Malik, Singroha. Cont.: 7015420969, 9896813684
- SM4 Jat Girl (DOB 25.05.95) 25/5'2" Graduation in Veterinary Science from Chennai. Father employed in Air Force. Mother housewife. Brother software Engineer. Family settled at Ambala. Avoid Gotras:Bhanwala, Duhan, Chahal. Cont.: 8708133478, 8059128626

हम जैसा बोते है, वैसा काटते हैं। हम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। –स्वामी विवेकानंद

- SM4 Jat Girl (DOB 25.10.92) 28/5'5" B.Tech (Electronics & Communication.) Avoid Gotras: Dhayal, Punia, Phogat. Cont.: 9416270513
- SM4 Jat Girl Divorcee (DOB 23.07. 88) 32/5'3" BDS. Own practice. Father VRS from Revenue Department & own business. Mother housewife. Avoid Gotras: Chahar, Nain, Binda. Cont.: 7347378494, 9414465295
- SM4 Jat girl (DOB 24.11.92) 28/5'2" M.Com from P.U. Chandigarh. Working in Electricity Board Haryana at Panchkula on adhoc basis. Avoid Gotras: Pawar, Dahiya, Pilania. Cont.: 9417723184, 9780325534.
- SM4 Jat Boy 26/5'8" B.A., M. A. first year. Own business. Avoid Gotras:Malik, Dalal, Ghanghas. Cont.: 9041314951.
- SM4 Jat Boy (DOB 18.08.91) 28/6 feet MBA in H.R & Marketing. Avoid Gotras: Rana, Joon, Aatil. Cont.: 8264865639, 7087501598
- SM4 Jat Boy 30/5'8" B.Tech. Working in I.T. Company for last four year. Avoid Gotras: Malik, Khatri, Dahiya. Cont.: 9463491567
- Suitable match for Jat Boy (DOB March 92) 28/5'9" B.Sc. (Computer Science) from Punjab University, Pursuing MCA. Employed in Kurukshetra University Kurukshetra as Clerk on regular basis. Father in private job. Mother housewife. Sister married and employed in Punjab Government. Family settled in Mohali. Preferred match in Government job. Avoid Gotras: Jadge, Budhrain. Cont.: 9056787532.
- SM4 Jat Boy 29/5'9" B.A. Own business of readymade garments. . Avoid Gotras:Sidhu, Ghuman. Cont.: 8054445234
- SM4 Jat Boy (DOB 06.08.91) 29/5'6" B. Tech. in ECE. Working in MNC in Chandigarh with 12.5 lakh package PA. Father retired from PSU. Own house and commercial plot in Panchkula Distt.. Preferred working urban living family girl. Avoid Gotras: Dahiya, Ruhella, Ruhil. Cont.: 9467806085, 7206328529
- SM4 Jat Boy (DOB 12.11.94) 26/5'11" Employed as J.E. in Municipal Corporation Chandigarh. Preferred match from Tri-city with Govt. job. Avoid Gotras: Malik, Redhu, Grewal. Cont.: 8168312760
- SM4 Jat Boy 29/6 feet. M.com, NET, GRF cleared three times. Employed in Kurukshetra University on contract basis. Mother professor in Govt. College. Father retired from Haryana Govt. Own house at Panchkula and Gurgaon. Avoid Gotras: Sangwan, Malik, Dhanda. Cont.: 7015108785
- SM4 Jat Boy (DOB 13. 04.93) 27/5'11". B.Tech in Computer Science from SRM College Chennai. Father Army Ex-service man. Mother housewife. Avoid Gotras:Dalal, Kadian, Gawadiya.Cont.: 8054064580
- SM4 Jat Boy (DOB 17.03.93) 27/5'10". B.A. Own house at Bhiwani. Ten acre agriculture land at village. Father in Govt. service. Avoid Gotras:Nain, Sangwan, Dhaliwal, Panghal. Cont.: 7837908269
- SM4 Jat Boy (DOB February 93) 27/6'1". B. Tech Mechanical Engineering. Job in SSWL. Father retired from Govt. service. Avoid Gotras:Nehra, Kadyan, Dhull, Malik, Hailwat, Saroya, Dalal. Cont.: 9877996707
- SM4 Jat Boy (DOB 05.08.93) 27/5'8" Degree in B.V.S.C. Employed as Veterinary Surgeon in Haryana government on contract basis. Avoid Gotras:Gahlayan, Malik, Boora. Cont.: 9468411784, 9350963667
- SM4 Jat Boy (DOB18.10.93) 27/5'10" B.Tech. in Civil Engineering. Own construction work. Father retired from Haryana government. Avoid Gotras: Dahiya, Gehlawat, Hooda, Rathi. Cont.: 9888502076
- SM4 Jat Boy (DOB15.11.91) 29/5'9" M.A. LLB, Doing practice in District Court. NET, JRF clear, pursuing Phd. Father Deputy District Attorney in Haryana Government. Own house at Hisar. 20 acre agriculture land at village. Avoid Gotras: Kajla, Punia. Cont.: 9992900936
- SM4 Jat Boy (DOB18.10.90) 30/6'1" B. Tech from UIET Chandigarh. Employed as Inspector in CBI. Own house at Zirakpur. Preferred employed match in Centre or state govt. Avoid Gotras: Khasa, Dahiya, Lathwal. Cont.: 9023492179, 7837551904
- SM4 Jat Boy (DOB 26.09.91) 29/5'8" B.A. LLB, Doing practice as Advocate in Punjab & Haryana High Court. Pursuing judiciary. Only son. Three house at Chandigarh, Panchkula, Hisar,. Three acre land in village. Three shops and plots. Avoid Gotras: Punia, Nain, Sihag. Cont.: 9316131495, 7973059762
- SM4 Jat Boy (DOB 27.04.89) 31/5'10" B.Tech. in Bio-Medical Engineering. Working in a reputed Master's Medical Company with package of Rs. 16.5 lacs PA. Father businessman. Mother housewife. Avoid Gotras: Jatyan, Duhan, Dagar. Cont.: 9818724242
- SM4 Jat Boy (DOB 14.03.95) 25/5'10" B.A. Doing M.A. Employed as clerk in Municipal Corporation Chandigarh on contract basis. Own house at Panchkula. Avoid Gotras: Sangwan, Jakhar, Pachar. Cont.: 9463961502
- SM4 Jat Boy (DOB 08.10.91) 29/5'9" B. Tech. in Mechanical Engineering. Employed in a reputed Company as Senior Engineer. Family settled at Pinjore. Avoid Gotras: Malik, Balyan. Cont.: 9466015020
- SM4 Jat boy (DOB 15.11.95) 25/6'1" Employed as Nursing Officer in ESI hospital, Govt. of India in U.P. with salary of Rs. 75000/- PM. Preferred employed girl. Avoid Gotras: Bhanwala, Mann, Khatkar. Cont.: 9417579207
- SM4 Jat Boy (DOB January 89) 31/5'8" B.Tech Electronics, MBA. Self business. Avoid Gotras: Mor, Panchal, Rathi. Cont.: 9468457144.

16 फरवरी, 2021 को बसन्त पंचमी के आयोजन के संबंध में

आप सभी को सूचित किया जाता है कि जाट सभा चण्डीगढ़ एवं पंचकूला की कार्यकारिणी ने 09 जनवरी 2021 को आयोजित कार्यकारिणी की मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस वर्ष कोविड–19 महामारी के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा–निदेर्शों व प्रोटोकॉल की पालना करते हुये जाट सभा द्वारा 16 फरवरी 2021 को बंसन्त पंचमी एवं दीन बंधु चौ० छोटूराम का 140वां जन्म दिवस धूमधाम से उत्सव के तौर पर नहीं मनाया जायेगा और इस दिन दीनबंधु चौ० छोटूराम की प्रतिमा पर श्रृद्धा सुमन अर्पित करके भावमीनी श्रृद्धाजंली दी जायेगी।

अतः जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे 16 फरवरी 2021 को प्रातः 11 बजे जाट भवन, सैक्टर–27, चण्डीगढ़ में "दीन बंधु" को श्रृद्धाजंली देने हेतु उपस्थिति होने की कृपा करें। जाट सभा के आजीवन सदस्य व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस संक्षिपत कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

कार्यकारिणी
जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला

अमृत और मृत्यु दोनों ही इस शरीर में स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। –वेद व्यास

आर्थिक अनुदान की अपील

आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि जाट सभा चंडीगढ़ द्वारा 6 जून 2019 को गांव कोटली बाजालान–नोमैई कटरा जम्मु में जी टी रोड़ पर 10 कनाल भूमि की भू–स्वामी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बदरी नाथ निवासी गांव कोटली बाजालान, कटरा, जिला रियासी (जम्मु) के साथ लंबी अवधि के लिए लीज डीड पंजीकृत की गई है। इस भूमि का इंतकाल भी 6 जुलाई 2019 को जाट सभा चंडीगढ़ के नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार इस भूमि पर जाट सभा चंडीगढ़ का पूर्ण स्वामीत्व स्थापित हो चुका है। बिल्ड़िग के मजबूत ढ़ांचे/निर्माण के लिये साईट से मिट्टी परीक्षण करवा लिया गया है और बिल्ड़िंग के नक्शे/ड्राईंग पास करवाने के लिये सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिये गये है। इसके अलावा जम्मु प्रशासन व माता वैष्णों देवी साईन बोर्ड कटरा को यात्री निवास साईट पर जरूरी मूल भूत सार्वजनिक सेवायें – छोटे बस स्टैड़, टू–व्हीलर सैल्टर, सार्वजनिक शौचालय, वासरूम, पीने के पानी का स्टाल आदि के निर्माण हेतु पत्र लिखकर निवेदन किया गया है।

जाट सभा द्वारा यात्री निवास भवन का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का प्रयास था लेकिन कोविड़–19 महामारी के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका और इस महामारी का जाट सभा की वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है। जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला यात्री निवास भवन का निर्माण करने पर वचनबद्ध है और वर्ष 2021 के शुरू में निर्माण शरू कर दिया जायेगा।

यात्री निवास भवन का शिलान्यास व दीन बंधु चौधरी छोटू राम की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण 10 फरवरी 2019 को बसंत पंचमी उत्सव एवं दीन बंधु चौधरी छोटूराम की 136वीं जयंती समारोह के दौरान महामहिम राज्यपाल, जम्मु काश्मीर माननीय श्री सत्यपाल मलिक द्वारा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीएमओ डा० जितेंद्र सिंह व जाट सभा के अध्यक्ष एवं हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक डा० एम एस मलिक, भा०पु०से० (सेवा निवृत) की उपस्थिति में संपन्न किया गया।

यात्री निवास भवन एक लाख बीस हजार वर्ग फुट में बनाया जाएगा जिसमें फैमिली सुईट सहित 300 कमरे होगें। भवन परिसर में एक मल्टीपर्पज हाल, कांफ्रैंस हाल, डिस्पैंसरी, मैडीकल स्टोर, लाईब्रेरी, बच्चों की प्रतिभा विकास एवं विभिन्न व्यवसायिक व सुरक्षा संबंधी सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगीं। सुरक्षा सैनिकों, शहीद परिवारों व उनके आश्रितों के लिए मुफत ठहरने तथा माता वैष्णों देवी के श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगीं।

आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस कल्याणकारी व पुनित सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा अनुसार शीघ्र अनुदान देने की कृपा करें ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके जोकि आज सभी के सहयोग से ही संम्भव हो सकेगा। यदि कोई दानी सज्जन यात्री निवास में कमरे के निर्माण हेतू 5 लाख रूपये या इससे अधिक की राशि दान देता है तो उसका नाम भवन परिसर में उचित स्थान पर अंकित किया जाएगा और उसे भवन में आजीवन मुफ्त ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जम्मु काश्मीर के भाई–बहन व दानवीर सज्जन इस संबंध में चौधरी छोटु राम सेवा सदन के अध्यक्ष श्री सर्बजीत सिंह जोहल (मो०नं० 9419181946), श्री भगवान सिंह उप प्रधान (मो०नं० 8082151151) व केयर टेकर श्री मनोज कुमार (मो०नं० 9086618135) पर संपर्क कर सकते हैं। यात्री निवास भवन के लिए अनुदान देने वाले सज्जनों का उचित विवरण रखा जाएगा और उनका नाम जाट सभा द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'जाट लहर' में भी प्रकाशित किया जाएगा। भवन निर्माण की अनुदान राशि चैक, डिमांड ड्राफट द्वारा 'जाट सभा चंडीगढ़' के पक्ष में जाट भवन 2–बी, सैक्टर 27–ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ में भेजी जा सकती है अथवा आर टी जी एस की मार्फत सीधे जाट सभा के बचत खाता नंबर 50100023714552, आईएफएससी कोड– एचडीएफसी 0001324 में ट्रांसफर की जा सकती है।

अनुदान की राशि आयकर अधिनियम की धारा 80–जी के तहत आयकर से मुक्त है।

निवेदक : कार्यकारिणी जाट सभा चंडीगढ़/पंचकुला,
चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

सम्पादक मंडल

सरंक्षक एवं सम्पादक : **डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)**
सह–सम्पादक : डा० राजवन्तीमान
साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक
प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो० : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो० : 9416282798
वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़

जाट भवन 2–बी, सैक्टर 27–ए, चण्डीगढ़
फोन : 0172–2654932 2641127
Email: jat_sabha@yahoo.com; Website: www.jatsabha.org

सर छोटूराम जाट भवन, सैक्टर–6, पंचकूला
फोन : 0172–2590870, Email: jatbhawan6pkl@gmail.com

चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

Postal Registration No. CHD/0107/2021-2023

RNI No. CHABIL/2000/3469

मुद्रक प्रकाशन एवं सरंक्षक सम्पादक डा. एम. एस. मलिक ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोशियटिड प्रिन्टर्ज, चंडीगढ़, फोन : 0172-2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2-बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27-ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया।